E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

मध्यप्रदेश में जनजातियों के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं का मूल्यांकन: सहरिया जनजाति के परिप्रेक्ष्य में चंबल संभाग का अध्ययन

रिचा कुशवाह

शोध छात्रा,राजनीति शास्त्र,
जीवाजी विश्व विद्यालय
ग्वालियर,(म.प्र.)

डॉ. जयश्री त्रिवेदी

प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष,
राजनीति शास्त्र,
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दतिया (म.प्र.)

Paper Rcevied date

05/05/2025

Paper date Publishing Date

10/05/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.15586396

IMPACT FACTOR
5.924

Abstract

यह अध्ययन मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, जिसमें चंबल संभाग की सहरिया जनजाति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह (PVTG) के रूप में पहचाने जाने वाले सहरिया समुदाय को पुरानी सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य असमानताओं का सामना करना पड़ता है। शोध में श्योपुर, मुरैना और शिवपुरी जिलों में साक्षरता, पोषण, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, आजीविका और आवास जैसे प्रमुख मापदंडों को शामिल किया गया है | अनुभवजन्य डेटा चिंताजनक संकेतक प्रकट करते हैं: केवल 23.2% समग्र साक्षरता और महिला साक्षरता काफी कम है, 90% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं और 59.1% बच्चे कम वज़न के हैं । तपेदिक की घटना 1518 प्रति 1,00,000 है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। डलछत्म्ला, वन अधिकार अधिनियम (FRA), और आदिवासी उप योजना (TSP) जैसे कार्यक्रमों के बावजूद, केवल 58% सहरिया किसान ही कोई लाभ बताते हैं और 71% निरक्षर बने हुए हैं, जिससे जागरूकता और योजनाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है । क्षेत्र अवलोकन भ्रष्टाचार, प्रशासनिक देरी, दस्तावेज़ अनुपलब्धता और कम सामुदायिक भागीदारी जैसी कार्यान्वयन बाधाओं का संकेत देते हैं । महिलाओं को दोहरा बोझ उठाना पड़ता है, फिर भी वे निर्णय लेने की भूमिकाओं से बाहर रहती हैं। मिट्टी का कटाव और भौगोलिक अलगाव जैसे पारिस्थितिक कारक प्रगति में और बाधा डालते हैं । यह शोधपत्र सहरिया बोली में स्थानीय जागरूकता, एनटीएफपी - आधारित सूक्ष्म उद्योग, महिला-केंद्रित स्वास्थ्य और पोषण अभियान और सामुदायिक कौशल विकास केंद्रों की सिफारिश करता है। सार्थक समावेशन और दीर्घकालिक आदिवासी सशक्तीकरण के लिए एक सहभागी, सांस्कृतिक रूप से सैरेखित और पारदर्शी ढांचा आवश्यक है।

मुख्यबिन्दु: सहरिया जनजाति, चंबल संभाग, आदिवासी विकास योजनाएँ, मनरेगा, प्रशासनिक बाधाएँ

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

प्रस्तावना

सहरिया जनजाति को भारत की सबसे प्राचीन और हाशिये पर पड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक माना जाता है, जो मुख्य रूप से उत्तरी मध्य प्रदेश के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहती है, खासकर श्योपुर, मुरैना और शिवपुरी जैसे जिलों के साथ-साथ राजस्थान के पड़ोसी क्षेत्रों में भी। माना जाता है कि सहरियाः नाम की उत्पत्ति फारसी शब्द सेहर से हुई है, जिसका अर्थ है : जंगल के निवासीः, जो उनकी पारंपरिक वन - आधारित आजीविका और पारिस्थितिक अभिविन्यास को सटीक रूप से दर्शाता है (शर्मा और तिवारी, 2007)। सामाजिक रूप से, सहरिया एक पितृसत्तात्मक और कबीले - आधारित संरचना का पालन करते हैं, जहाँ परिवार अक्सर सहराना नामक कॉम्पैक्ट बस्तियों में रहते हैं। इनमें लगभग 15-30 झोपड़ियाँ होती हैं और इनका संचालन पटेल नामक समुदाय के एक बुजुर्ग द्वारा किया जाता है।

जनजाति संयुक्त परिवार में रहती है और सामूहिक निर्णय लेने, सहयोग और बड़ों के प्रति सम्मान पर जोर देती है (भसीन, 2000)। उनका समाज कई बहिर्विवाही कुलों में विभाजित है, जो अक्सर प्रकृति में कुलदेवता के होते हैं, जो वनस्पतियों और जीवों से जुड़े होते हैं, जो प्रजातियों के संरक्षण की पारिस्थितिक नैतिकता को बढ़ावा देते हैं (जैन, 1988)। सांस्कृतिक रूप से, सहरिया समुदाय जीवंत है और मौखिक परंपराओं में गहराई से निहित है। लोकगीत, गवरी जैसे नृत्य और ढोल और मंजीरा जैसे संगीत वाद्ययंत्र उनके उत्सवों और अनुष्ठानों के केंद्र में हैं। वे दिवाली और होली जैसे मुख्यधारा के हिंदू त्योहारों और नवाखानी जैसे पारंपरिक समारोहों का पालन करते हैं, जो नई फसल का जश्न मनाते हैं। भाषा के लिहाज से, जबकि अधिकांश अब हिंदी की स्थानीय बोलियाँ बोलते हैं, पुरानी पीढ़ी अभी भी सहरालिया का उपयोग करती है, जो अद्वितीय ध्वन्यात्मक लक्षणों वाली एक आदिवासी भाषा है (जोशी, 1986)।

आधुनिक आजीविका में निर्माण और ईंट भट्टा श्रम को शामिल करने के लिए विविधता आई है, लेकिन गरीबी और खाद्य असुरक्षा पुरानी समस्याएं बनी हुई हैं (त्यागी और पाधी, 2019)। आनुवंशिक रूप से, अध्ययनों ने एचएलए - डीआरबी 1' एलील के उच्च प्रचलन को दिखाया है, जो तपेदिक जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता का सुझाव देता है, कम उम्र में शादी होना आम बात है, और सिंदूर लगाना और सामुदायिक भोज जैसी प्रतीकात्मक रस्में विवाह समारोहों का अभिन्न अंग हैं। विधवा पुनर्विवाह सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, और संपत्ति का उत्तराधिकार पितृवंशीय है, जिसमें बेटे प्राथमिक उत्तराधिकारी होते हैं (पांडे, 1988)। सहरिया जनजाति प्रकृति पूजा, कबीले की एकता और मौखिक परंपराओं द्वारा आकार दी गई एक विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान बनाए रखती है, भले ही आधुनिकता धीरे-धीरे उनके जीवन के तरीके को प्रभावित करती है। उनकी लचीलापन और गहरी सांस्कृतिक जड़ें उन्हें भारत की आदिवासी विरासत का एक महत्वपूर्ण घटक बनाती हैं

अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त परिचय

भारत में जनजातीय समुदायों का विकास एक दीर्घकालिक एवं बहुस्तरीय प्रक्रिया रहा है, जिसमें विशेष रूप से सहरिया जनजाति जैसे हाशिये पर स्थित समूहों को सामाजिक-आर्थिक मुख्यधारा में लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं (ठाकुर और शर्मा, 2012)। इन प्रयासों का उद्देश्य भौगौलिक अलगाव, आर्थिक अभाव, और स्वास्थ्य तथा पोषण जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना है (घोष - जेरथ एट अल 2013)। मध्यप्रदेश के चंबल क्षेत्र में निवास करने वाली सहरिया जनजाति इन सभी कारकों से प्रभावित एक प्रमुख विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) है, जो आज भी कई सामाजिक और आर्थिक संकटों से जूझ रही है।

सहरिया समुदाय को कुपोषण, तपेदिक (टीबी), गरीबी और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में किए गए एक पोषण संबंधी अध्ययन में सहरिया समुदाय में क्रोनिक ऊर्जा की कमी और बाल कुपोषण की उच्च दर पाई गई, जो लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता को स्पष्ट करता है (घोष - जेरथ एट अल., 2013)। तपेदिक, विशेषकर दवा - प्रतिरोधी प्रकार, इस समुदाय में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभरा है, जो कुपोषण, धूम्रपान और सामाजिक स्थितियों के कारण और भी गंभीर हो गया है (राव एट अल., 2010; प्रकाश एट अल., 2016)। यह स्थिति दर्शाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और पोषण सहायता जैसी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन इस जनजाति के लिए अत्यावश्यक है।

सरकार द्वारा आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही योजनाएँ, जैसे कि इको-पर्यटन परियोजनाएँ, सहरिया जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और आजीविका के नए विकल्प उपलब्ध कराने के प्रयास हैं (श्रीवास्तव, 2016)। हालांकि, संरचनात्मक चुनौतियाँ जैसे अविकसित स्वास्थ्य अवसंरचना, सीमित बाजार पहुँच, और दूरदराज क्षेत्रों में योजनाओं की सीमित पहुँच इन पहलों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

चंबल संभाग का परिचय और भूगोल

प्राचीन और मध्यकालीन काल।

चंबल क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व प्राचीन काल से है, जिसका उल्लेख महाकाव्य महाभारत मंह मिलता है। किंवदंती के अनुसार, दशपुरा (वर्तमान मंदसौर) के राजा रंतिदेव ने ब्राह्मणों को भोजन और मवेशी वितरित करके प्रसिद्धि प्राप्त की। इन मवेशियों की खाल से एक नदी बनी, जिसके कारण चंबल नदी का नाम 'चर्मणवती' पड़ा। लोककथाओं से पता चलता है कि कौरवों और पांडवों के बीच पासा का कुख्यात खेल नदी के तट पर हुआ था, जहाँ द्रौपदी के श्राप ने नदी को अपवित्र कर दिया था। (बींउइंसेंतिप. बवउ) प्रारंभिक मध्यकालीन काल के दौरान, इस क्षेत्र पर गुप्तों और बाद में गुर्जर-प्रतिहारों और उसके बाद कच्छपघाटों का शासन था। ये राजवंश कला और वास्तुकला के संरक्षक थे, जिन्होंने कई मंदिर और शिलालेख बनवाए जो क्षेत्र के इतिहास के पुनर्निर्माण में अमूल्य रहे हैं। मुरैना के निकट बटेश्वर मंदिर परिसर, जिसमें शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित लगभग 200 बलुआ पत्थर के मंदिर हैं, 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच के गुर्जर-प्रतिहार काल की स्थापत्य कला का उदाहरण है। 1 9वीं शताब्दी में, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, चंबल क्षेत्र मध्य भारत एजेंसी का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने वर्तमान चंबल संभाग के गठन का नेतृत्व किया, जिसमें मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों को मुरैना में प्रशासनिक मुख्यालय के तहत समेकित किया गया।

डाकुओं का युग

चंबल घाटी 20वीं शताब्दी में डाकुओं या डाकुओं को शरण देने के लिए कुख्यात हो गई, जो इस क्षेत्र के बीहड़ इलाकों और भूलभुलैया वाले बीहड़ों का इस्तेमाल छिपने के लिए करते थे। फूलन देवी जैसी शख्सियतों सहित ये अपराधी दशकों तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चुनौती देते हुए डकैती और हिंसा की घटनाओं में लिप्त रहे। इस क्षेत्र की स्थलाकृति, गहरी खाइयों और घने जंगलों की विशेषता है, जो प्राकृतिक आश्रय प्रदान करती है, जिसमें अधिकारियों के लिए प्रवेश करना मुश्किल था। डकैती का प्रचलन सामाजिक-आर्थिक कारकों से जुड़ा था, जिसमें सामंती शोषण और रोजगार के अवसरों की कमी शामिल थी, जिसने कुछ व्यक्तियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया।

भूगोलिक विवरण

चंबल संभाग भारत के मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र है। इसमें तीन जिले शामिल हैं: मुरैना, भिंड और श्योपुर। भौगोलिक दृष्टि से, यह संभाग लगभग 16,054 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 25°15' से 26° 48' उत्तरी अक्षांश और 76° 31' से 79°15' पूर्वी देशांतर (चंबल संभाग की आधिकारिक वेबसाइट) के बीच स्थित है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक और प्रशासनिक सीमाओं से घिरा हुआ है: उत्तर और उत्तर-पश्चिम में, यह चंबल नदी से घिरा हुआ है, जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ सीमाओं का भी सीमांकन करती है; पूर्व में मध्य प्रदेश के दतिया जिले और उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से सटा हुआ है; दक्षिणी सीमा शिवपुरी और ग्वालियर जिलों से जुड़ती है, जबकि पश्चिमी छोर पार्वती नदी और राजस्थान से मिलता है। यह रणनीतिक स्थान चंबल क्षेत्र को पारिस्थितिक और प्रशासनिक दोनों तरह से महत्व देता है।

दक्षिणी और दक्षिण - पूर्वी क्षेत्र मालवा और विंध्य पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित हैं, जिनकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई लगभग 300 मीटर है, जबकि चंबल नदी के साथ उत्तरी खंड लगभग 160 मीटर की औसत ऊँचाई के साथ चंबल घाटी में उतरता है। गंभीर मिट्टी के कटाव से काफी हद तक आकार ले चुका है, जिसने विशाल बंजर भूमि या खड्डों का निर्माण किया है, जिन्हें स्थानीय रूप से 'बीहड़' (मुरैना जिला वेबसाइट) कहा जाता है। ये खड्ड एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता हैं और देश में सबसे बड़े और सबसे अधिक क्षरण वाले परिदृश्यों में से हैं, जो सदियों से वनों की कटाई, अतिचारण और अस्थिर भूमि उपयोग प्रथाओं (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, 2013) से उत्पन्न हुए हैं।चंबल संभाग की स्थलाकृति में पठारों और घाटियों का समावेश है, जिसमें चंबल घाटी की बीहड़ भूमि विशिष्ट है। बीहड़ मिट्टी के अत्यधिक कटाव से बनी बंजर घाटियाँ हैं, जो दशकों से वनों की कटाई, अतिचारण और अस्थिर भूमि उपयोग के परिणामस्वरूप बनी हैं। यहाँ की प्रमुख नदी चंबल है, जो जल निकासी के

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

साथ-साथ राज्य की सीमा भी निर्धारित करती है। क्षेत्र की जलवायु अर्ध-शुष्क है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल, ठंडी सर्दियाँ और मानसून के दौरान औसतन 862.6 मिमी वर्षा होती है।

इस क्षेत्र में वनस्पति इसकी शुष्क जलवायु और खराब मिट्टी के कारण विरल है। प्रमुख वनस्पतियों में कांटेदार झाड़ियाँ और छोटे सूखा-प्रतिरोधी पेड़ जैसे कि बबूल निलोटिका, बबूल सेनेगल, बैलेनाइट्स एजिपियाका, कैरि सेपियारिया और कैपरिस डेसीडुआ शामिल हैं। नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र अतिचारण और खराब कृषि पद्धतियों के कारण और भी अधिक तनावपूर्ण हो गया है, जिससे वन विकास सीमित हो गया है और बहाली के प्रयास और अधिक कठिन हो गए हैं (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, 2013)। नदी के किनारे की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ है, जो गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा और दालों जैसी फसलों को सहारा देती है, जिसमें सरसों वाणिज्यिक महत्व की एक प्रमुख फसल है।

चूना पत्थर कैलारस क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त कांच की रेत के भंडार धनेला गाँव में नूराबाद के पास स्थित हैं। चंबल घाटी में भारतीय हिरन (चिंकारा), नीलगाय (नीला बैल), जंगली सूअर, सियार, लकड़बग्घा, मोर, खरगोश, लोमड़ी, साही, भेड़िये, चित्तीदार हिरण और सांभर हिरण जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैले राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की मौजूदगी इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी मूल्य में इजाफा करती है। यह अभयारण्य घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिक्स), गंगा डॉल्फ़िन और भारतीय स्कीमर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, और 300 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियों का घर है, जिनमें स्थानीय और प्रवासी दोनों शामिल हैं।

जनजातीय विकास पर हुए पूर्व शोध

भारत में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु कई नीतियाँ और योजनाएँ लागू की गई हैं, परंतु अब भी उनकी आजीविका पारंपरिक तरीकों पर निर्भर है। जनजातीय समुदायों के लिए आय में वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाने पर जोर दिया गया है (ठनचजं, 2018)। मध्यप्रदेश में भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी पाई जाती है, जिनमें प्रमुख हैं: गोंड, भील, बैगा, कोरकू, और सहारिया। राज्य सरकार ने इन समुदायों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं जैसे कि आय-वर्धन, कौशल विकास, और विशेष पिछड़ा जनजातीय समूहों के लिए कार्यक्रम (IJCRT, 2015)। पातालकोट (छिंदवाड़ा जिला) में औषधीय पौधों के व्यापार से जुड़े जनजातीय विक्रेताओं की आय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से बढ़ी है। इससे पता चलता है कि क्षेत्रीय कौशल आधारित योजनाएं जनजातीय आजीविका में सुधार ला सकती हैं (Khare 2022).

सत्यापन और त्रिभुजन

विभिन्न स्रोतों से डेटा को क्रॉस-सत्यापित करके त्रिभुजन किया जाता है सर्वेक्षण परिणाम, साक्षात्कार, फील्ड नोट्स और द्वितीयक डेटा। उदाहरण के लिए, साक्षात्कार में किए गए दावों की तुलना फील्ड अवलोकन और सरकारी दस्तावेज़ों से की जाती है। यह स्थिरता सुनिश्चित करता है, विश्वसनीयता को मजबूत करता है और निष्कर्षों की प्रामाणिकता को मान्य करता है। अनुवर्ती यात्राओं या चर्चाओं के माध्यम से पुनः जाँच करके विरोधाभासों को संबोधित किया जाता है

निष्कर्ष और सुझाव

इस अध्ययन के निष्कर्ष मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में सहरिया जनजाति द्वारा सामना की जा रही लगातार सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौतियों को उजागर करते हैं। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (चटज्ल) के रूप में पहचाने जाने के बावजूद, सहरिया समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्थायी आजीविका तक सीमित पहुँच के साथ प्रणालीगत हाशिए पर रखा जाना जारी है | हालाँकि कई केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाएँ जैसे कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), और जनजातीय उप योजना (TSP) का उद्देश्य जनजातीय आबादी का उत्थान करना है, लेकिन उनका ज़मीनी क्रियान्वयन खंडित और अपर्याप्त है। केवल 58% सहरिया लाभार्थियों ने कृषि योजनाओं से कोई ठोस सहायता प्राप्त करने की रिपोर्ट की है, और उनमें से भी, अधिकांश एक ही एजेंसी पर निर्भर हैं। 71% से अधिक निरक्षरता के साथ, समुदाय में पात्रता प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जागरूकता का अभाव है, जिससे उपलब्ध संसाधनों का कम

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

उपयोग होता है । प्रशासनिक अक्षमता, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, अपर्याप्त दस्तावेज (जैसे जाति प्रमाण पत्र और बैंक खाते) और वेतन वितरण में देरी से स्थिति और भी जटिल हो गई है। इसके अलावा, लिंग

आधारित असमानताएँ जारी हैं, जहाँ महिलाएँ घरेलू आय और दैनिक श्रम में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, लेकिन उन्हें प्रमुख निर्णय लेने वाली भूमिकाओं से बाहर रखा जाता है | भौगोलिक और पारिस्थितिक कारक जैसे कि क्षेत्र का ऊबड़-खाबड़ इलाका, खराब बुनियादी ढाँचा और अस्थिर प्रथाओं के कारण घटते वन क्षेत्र उनके अलगाव को और बढ़ा देते हैं। महिलाओं में 90% एनीमिया का प्रचलन, 59.1% कम वजन वाले बच्चे और प्रति 100,000 जनसंख्या पर 1518 टीबी के मामले जैसे पुराने मुद्दे प्रभावी हस्तक्षेप की तात्कालिकता को दर्शाते हैं।

सार्थक विकास हासिल करने के लिए, एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है । इसमें स्थानीय बोलियों में स्थानीय जागरूकता अभियान, कौशल - आधारित आजीविका प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, महिला-केंद्रित कल्याण योजनाएँ और प्रशासनिक स्तर पर बेहतर जवाबदेही शामिल हैं। दृष्टिकोण को सांस्कृतिक संवेदनशीलता, जमीनी स्तर की भागीदारी और नीतिगत इरादे और वास्तविक प्रभाव के बीच की खाई को पाटने के लिए निरंतर समर्थन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तभी विकास के प्रयास सहरिया समुदाय के लिए समावेशी, समतामूलक और टिकाऊ बन सकेंगे ।

References

1. (2015). The of Interntional Journal of Creative Research Thoughts of the paper economic development of tribals in madhyapradesh.
2. Bhandari, S. (2010). Tribal india's tryst with development.
3. Bhasin, V. (2000). Way of Life Among the Sahariya of Rajasthan
4. Bhatnagar, A. (2024). Political frameworks for tribal empowerment in india: successes, challenges, and recommendations. ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts. https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i5.2024.1612.
5. Biswas, R., & Kapoor, A. (2003). Fertility Profile of A Primitive Tribe, Madhya Pradesh. The 161 167. Anthropologist,5,https://doi.org/10.1080/09720073.2003.11890798.
6. Das, A., & Saha, A. (2016). Status of food security entitlements across particularly vulnerable tribal group (pvtg) pockets in jharkhand. Bmj Global Health, 1, A6-A7.
7. Dwivedi, D. (2016). Socio-economic impact of rural employment guarantee scheme in rewadistrict,madhyapradesh: a beneficiary perspective.
8. Fernandes, D. (2015). Implementation of MGNREGA & Its Impact on Rural Madhya Pradesh. The Indian Journal of Industrial Relations, 50, 505.
9. Ghosh-Jerath, S., Singh, A., Bhattacharya, A., Ray, S., Yunus, S., &Zodpey, S. (2013). Dimensions of nutritional vulnerability: assessment of women and children in Sahariya tribal community of Madhya Pradesh in India.. Indian journal of public health, 57 4, 260-7.
10. Gupta, V. (2018). Tribal Development in India - Status and Strategies. International Journal of African and Asian Studies, 48, 14-19.
11. Gurjar, P., Kumar, A., Shrivastava, S., Singh, L., Singh, C., & Hada, N. (2017). A study on agricultural schemes for saharia tribes in sheopur district of madhyapradesh.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

12. Jain, A. (1988). Tribal Clans in Central India and Their Role in Conservation
13. Jatav, R., &Ghanghat, S. (2023). Role of Non-Timber Forest Products (NTFPs) in the Livelihood in Sahariya Tribal Economy of Shivpuri district Madhya Pradesh, India. International Journal For Multidisciplinary Research. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05106.10295.
14. Joshi, R. (1986). Sahariyo ka nayajeevan.